No. GEN/XV/145/2025/ 829 Date: 30.03.2026

From : Registrar General,
Rajasthan High Court,
Jodhpur.

To : All the District & Sessions Judge,
Rajasthan.

Sub. : Regarding operationalize a dedicate payment facility for NI Act Cases in the light of the judgment dated 25.09.2025 passed by Hon'ble the Apex Court in Criminal Appeal No. 1755 of 2010, Sanjabij Tari Vs Kishore S. Borcar and Anr.

Ref. : Letter No. RHCB/CPC/eCourts/2026/144 dated 12.02.2026.

Sir,

With reference to the above cited subject, I am under direction to enclose herewith copy of the step-by-step process Manual for submission of cheque amount for the accused party alongwith the guidelines of Rajasthan Government for deface release with the request to circulate the same amongst all the District Courts for information and necessary action.

Further, you are requested to upload the same on the official website of your judgeship for public awareness.

Encl. As above.

30/03/26
REGISTRAR (ADMN.)

कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू

क्रमांक : स्था./2026/3612-39 दिनांक : 04.04.2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है– –

1. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, सं. 1 व 2, चूरू
2. श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चूरू
3. प्रभारी अधिकारी (लेखा) जिला न्यायालय, चूरू
4. विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी मामलात, चूरू
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू/नं. 1 व 2, राजगढ़/तारानगर/सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़
6. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चूरू
7. मुख्य/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू/राजगढ़/सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़
8. न्यायिक मजि. चूरू/राजगढ़/तारानगर/सरदारशहर/सुजानगढ़/बीदासर
9. अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, राजगढ़
11. लेखाशाखा, अदालत हाजा
12. सिस्टम ऑफिसर, अ.हाजा को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3639

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चूरू (राज.)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/e-GRAS-22/654-1053 दिनांक 13/4/2022

परिपत्र

विषयः– ऑनलाईन जमा हुए राजस्व के चालानों को विभाग द्वारा डीफेस किए जाने के पश्चात रिफण्ड के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान का परिपत्र दिनांक 01.11.2012, 10.09.2013 एवं पत्रांक 6899–7398 दिनांक 02.02.2016

ई–ग्रास पर जमाकर्ताओं को रिफण्ड में लगने वाले समय को कम करने एवं रिफण्ड प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए डीफेस किए हुए चालानों की राशि रिफण्ड (पूर्ण अथवा आंशिक) किए जाने हेतु संदर्भित पत्रांक 6899–7398 दिनांक 02.02.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में डीफेस हटवाने के लिए विभागाध्यक्ष को अधिकृत करते हुए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. डीफेस किए हुए चालान की राशि (पूर्ण अथवा आंशिक) के रिफण्ड हेतु जमाकर्त्ता से आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रकरण की पूर्ण जाँच कर ऐसे चालान पर अंकित डीफेस वाटर मार्क हटवाने (पूर्ण अथवा आंशिक) हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा ऑनलाइन विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
2. विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाधिकारी प्रकरण की जाँच कर डीफेस रिलीज के संबंध में अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित विभागाध्यक्ष को ऑनलाइन प्रेषित करेगें।
3. विभागाध्यक्ष अपने एच.ओ.डी. लॉगिन में डीफेस रिलीज हेतु उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप डीफेस रिलीज करने की कार्यवाही सम्पादित करेगें।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा हटाये गए चालान डीफेस की रिपोर्ट सिस्टम पर संबंधित कोषाधिकारी/ई–कोषाधिकारी को एवं संबंधित विभाग को उपलब्ध होगी।
5. विभागाध्यक्ष द्वारा हटाये गए डीफेस का अंकन चालान की प्रति पर वाटर मार्क के साथ दिया जाएगा।

उक्तानुसार चालानों के डीफेस रिलीज संबंधी नवीन प्रक्रिया दिनांक 01.06.2022 से प्रभावी होगी।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/e-GRAS-22/654-1053 दिनांक 13/4/2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर
8. ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय, वित्त भवन, जयपुर
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डीफेस रिलीज के संबंध में उक्त नवीन प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रावधान दिनांक 31.05.2022 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

PRE-TRIAL DEPOSIT OF CHEQUE AMOUNT BY THE ACCUSED IN CASES UNDER SECTION 138 OF THE N.I. ACT

In compliance with the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court of India in *Sanjabij Tari Vs. Kishore S. Borcar & Anr., 2025 INSC 1158*, decided on 25 September 2025, guidelines for the effective implementation of directions for the early disposal of cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 were issued vide **P.I. Circular No. 20/P.I./2025 dated 14.11.2025**. In the said guidelines, it has been directed that:

> **"3. Interim Payment Facility:** All District and Sessions Judges of each District Court shall create and operationalize dedicated online payment facilities through secure QR codes or UPI links. Since in the courts of Rajasthan the mechanism of making payments through QR Code and UPI pay link is not operational, therefore, until such dedicated online payment systems are created, the summons shall expressly state that the respondent/accused may deposit the cheque amount at the initial stage before the concerned Court. Upon confirmation of such payment, the Court shall inform the complainant and, upon confirmation of receipt, if appropriate, pass orders for release of such money and compounding/closure under Section 147 of the N.I. Act and/or Section 255 Cr.P.C./Section 278 BNSS, 2023."

Now, an online payment facility has been developed with the assistance of the Hon'ble e-Committee, Supreme Court of India for all courts in Rajasthan. A new payment type utility, namely **"138 NI Act Cases"**, has been made functional under the **"Other Payment" tab** on the e-Pay Portal. A parking budget head **8843-00-105-02-00** has been allotted for such deposits.

Accordingly, any accused person, after receiving the summons/notice of the Court regarding an offence under Section 138 of the N.I. Act, may deposit the cheque amount by using this utility. After providing an opportunity of hearing to the complainant, the Court shall pass appropriate orders regarding the release of such money and the disposal of the case. The released amount shall be paid from the above parking budget head in compliance with the order of the Court.

For the implementation of this online mechanism, certain directions may also be issued to all trial courts. Every summons issued by the Court should contain essential information such as details of the cheque including the amount, the URL of the e-Pay Portal, and brief directions regarding the process for depositing the cheque amount if the accused is willing to do so. The official e-mail ID of the Court may also be mentioned on the summons for further communication or for submitting proof of the said deposit.

For example, the following note may be endorsed on all summons:

> *"In compliance with the order passed by the Hon'ble Supreme Court in* **Sanjabij Tari v. Kishore S. Borcar & Anr., 2025 INSC 1158**, *if you so desire, you may visit the e-Pay Portal (URL: https://pay.ecourts.gov.in/) and, under the* ***'Other'*** *Payment tab, enter the case details and select the option* ***'138 NI Act Cases'*** *in the payment type to deposit the cheque amount of ₹…….. The payment receipt may thereafter be submitted to the Court through the official e-mail ID ……., or through any authorized person, or personally. The Court, after providing an opportunity of hearing to the complainant, shall pass an order in accordance with law regarding the deposited amount and the case."*

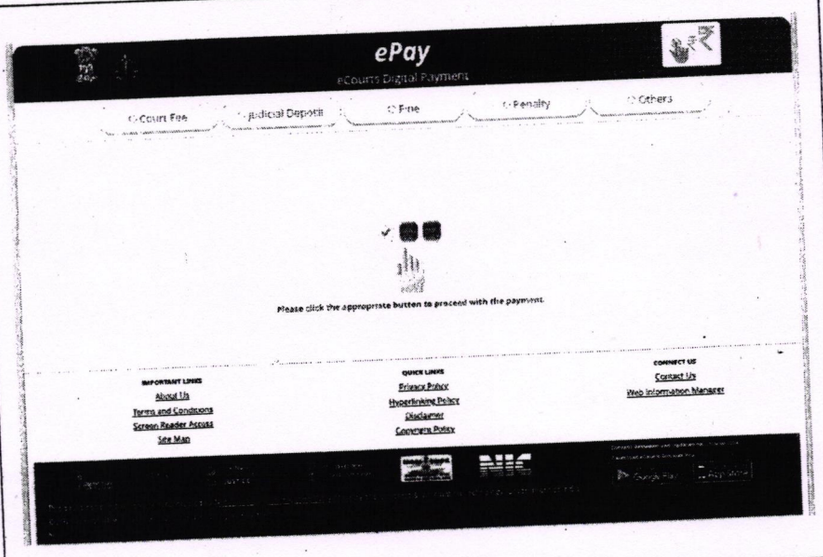
After depositing the said amount, the concerned party shall submit the receipt before the concerned Court, through any mode as directed, where it will be defaced. Thereafter, the Court shall provide an opportunity of hearing to the complainant and pass a judicial order regarding release of the deposited amount.

In compliance with any order directing payment of the said amount to any party, the deface shall first be released in accordance with **Letter No. F.5(प) DTA/IFMS/e-GRAS-22/654-1053, dated 13.04.2022** issued by the **Government of Rajasthan, Finance (Treasury & Accounts) Department (Copy Enclosed)**, or any other directions issued by the State Government from time to time through Head of Department (i.e. Rajasthan High Court). Thereafter, the deposited amount shall be paid to the concerned party through a refund bill. The step by step manual for the accused party for this activity is also mentioned here after. This manual may be given wide publicity by uploading on Official Website of all District Courts etc.

STEP BY STEP MANUAL FOR THE ACCUSED PARTY

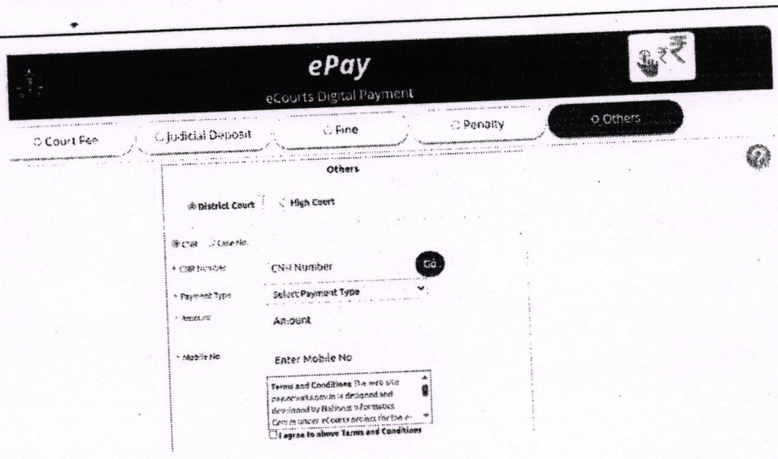
STEP - 1

किसी भी वेब ब्राउजर का उपयोग करते हुए ePay पोर्टल को open करें।
(URL: https://pay.ecourts.gov.in/)



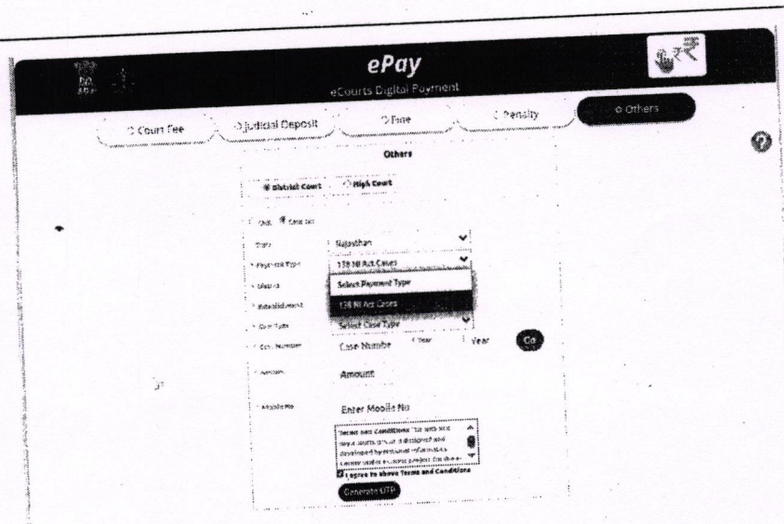
STEP - 2

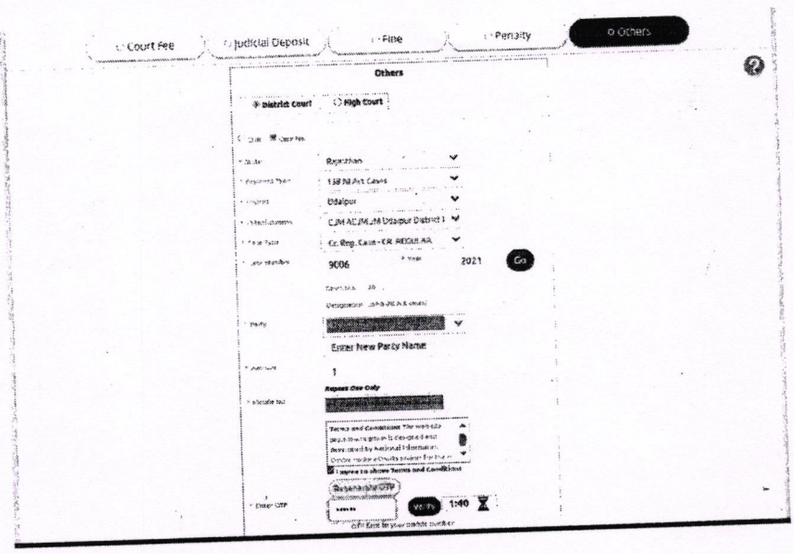
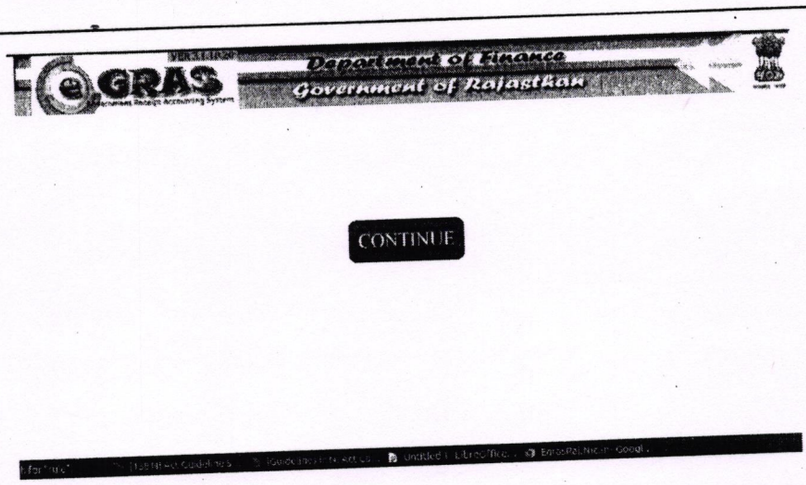
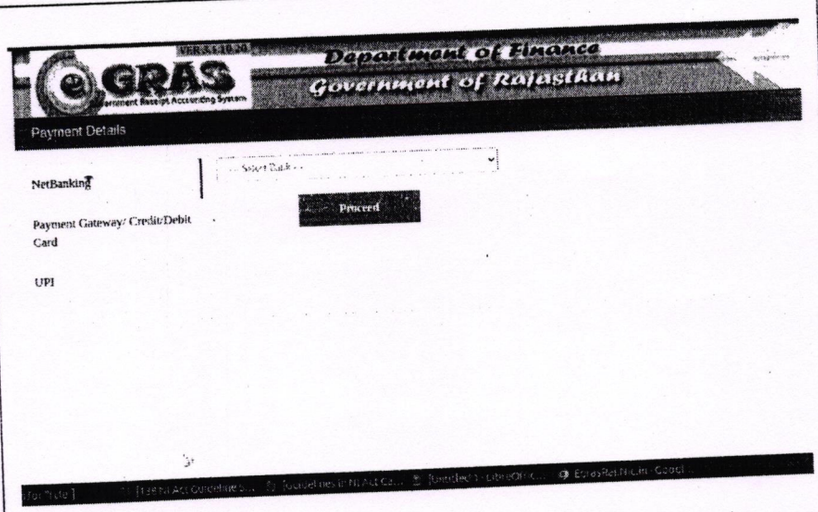
पोर्टल पर अंतिम मुख्य टेब "Other" को select करें।

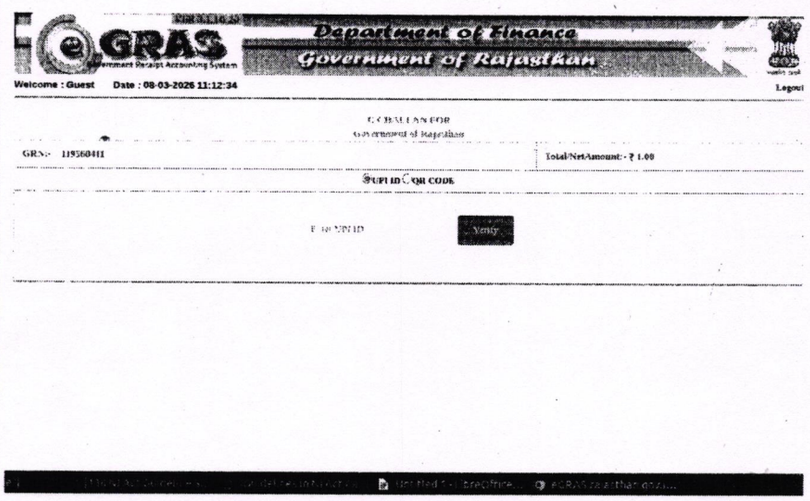
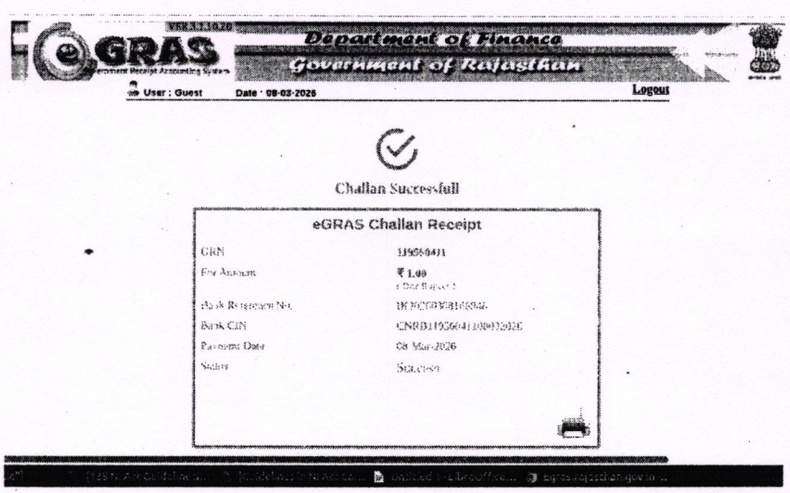
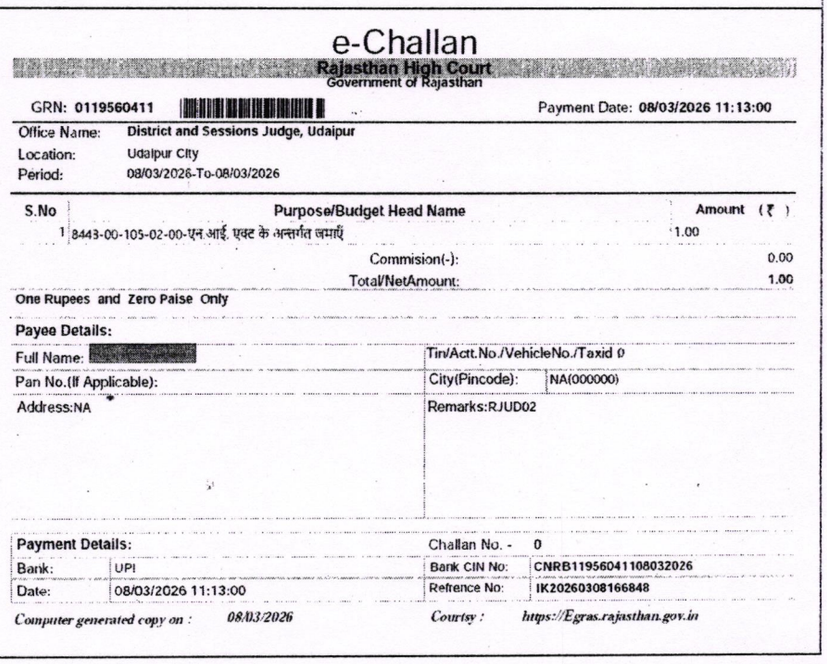


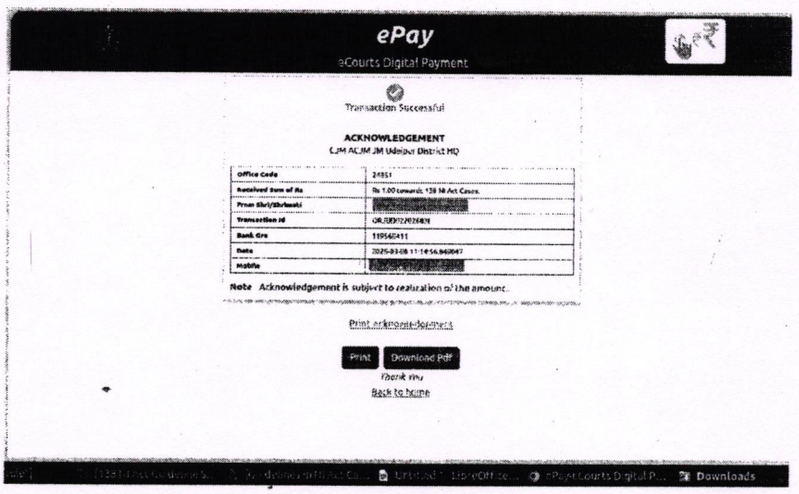
STEP - 3

"District Court" को select करें। CNR या Case No. में से एक को select करें। पेमेंट टाइप में 138 NI Act Cases को सलेक्ट करें। अपने केस के अनुसार बाकी प्रविष्ठियाँ अंकित कर Go बटन पर Click करें।



STEP - 4	
पक्षकार के रुप में स्वयं का नाम चुनें। यदि सूची में नाम नहीं आ रहा है तो Enter New Party Name Box में अपना नाम टाईप करें।. राशि व मोबाईल नंबर की प्रविष्ठियां करें। उक्त मोबाईल पर प्राप्त OTP को प्रमाणित करें।	
STEP - 5	
ePay पोर्टल यहाँ से eGRAS पोर्टल पर redirect होगा। Continue बटन पर Click करें।	
STEP - 6	
Payment Mode के लिए Net Banking, Card और UPI में से अपना विकल्प चुने।	

STEP - 7	
UPI की दशा में UPI ID अथवा QR Code को स्केन कर भुगतान किया जा सकता है।	
STEP - 8	
सफलतापूर्वक भुगतान होने पर eGRAS पोर्टल पर चालान रसीद generate होगी, जिसे प्रिण्ट आईकन से प्रिंट अथवा PDF डाउनलोड किया जा सकता है।	
STEP - 9	
डाउनलोड ई-चालान में GRN, बजट हेड, जमा राशि, दिनांक, समय, पक्षकार का विवरण इत्यादि का उल्लेख होता है।	

STEP - 10	
eGRAS पोर्टल से पुनः ePay पोर्टल पर redirect किया जायेगा, जहाँ से भी जमाकर्ता अपनी रसीद को प्रिंट या डाउनलोड कर सकता है।	
STEP - 11	
ePay पोर्टल की रसीद में समस्त जानकारी उपलब्ध होगी।	ACKNOWLEDGEMENT CJM ACJM JM Udaipur District HQ **Office Code** 24851 Received Sum of Rs Rs 1.00 towards 138 NI Act Cases. From Shri/Shrimati [redacted] Transaction Id ORJUD02202683L Bank Grn 119560411 Date 2026-03-08 11:14:56.849047 Mobile [redacted] **Note** : Acknowledgement is subject to realization of the amount.